TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 213
दि. 04.12.2025, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI   Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


## सीएम योगी की सख्ती के बाद बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों पर कसा शिकंजा, डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश

लखनऊ (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। इसके लिए नगर निकायों को सूची बनाकर आईजी और कमिश्नर को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दे दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और कमिश्नर व आईजी को सौपे।

कमिश्नर व आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं।

दिल्ली की तर्ज पर बनेंगे डिटेंशन सेंटर

उत्तर प्रदेश में से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही हैं। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। डिटेंशन सेंटरों पर खाने-पीने और इलाज की भी सुविधा-दिल्ली में करीब 18 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1500 विदेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त में रखा गया है। इनमें अवैध

रूप से सीमा पार करके आए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अफ्रीकी मूल के देशों के नागरिक हैं।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवा लेने की वजह से उनका सत्यापन कराया जा रहा है।

डिटेंशन सेंटरों पर खाने-पीने, इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी रहता है। तत्पश्चात एफआरआरओ (फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) के जरिए उनको वापस भेजने की प्रक्रिया की जाती है। तमाम राज्यों में पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की मदद से वापस भेजा जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया भी सभी राज्यों को भेजी है, जिसके बाद अब यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इनके प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी गृह विभाग को रोजाना देनी होगी।

## मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को गति देने वाले हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की

11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की गई

प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री का सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश

-: मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षित प्रोजेक्ट्स :-

- रेलवे के 6 प्रोजेक्ट्स - 4190.96 करोड़ रुपए
- उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स - 3657.62 करोड़ रुपए
- शहरी विकास विभाग के 12 प्रोजेक्ट्स - 3511.91 करोड़ रुपए

गांधीनगर,03 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को अधिक गति देने वाले 146 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के कामकाज की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक करने

का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री पटेल ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को गांधीनगर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कुल 11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की। इन प्रोजेक्ट्स अंतर्गत रेलवे से जुड़े 4, उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 और शहरी विकास विभाग के 15 प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन तथा समीक्षा हुई।

उन्होंने राज्य के ऐसे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की सर्वग्राही समीक्षा के उपक्रमों में अब तक तीन समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में लगभग 67 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के दौरान उनके दिए गए सुझावों के संदर्भ में सम्बद्ध विभागों द्वारा किए गए कामकाज पर भी इस चौथी समीक्षा बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 के विजन से सुसंगत विकसित गुजरात के लिए ये सभी विकासोन्मुखी हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पथदर्शक हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश बैठक में दिए।

इतना ही नहीं; उन्होंने बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा कि वे रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन से सम्बद्ध मामलों के त्वरित निवारण के लिए सम्बद्ध जिला कलेक्टरों को निर्देश दें।

## यूपी में घुसपैठियों पर योगी सरकार का 'सर्जिकल स्ट्राइक'!

## क्या है रोहिंग्या-बांग्लादेशी को खदेड़ने का 'एसआईआर' प्लान

(जीएनएस)।

कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य, जहां सीमापार से आने वाले अवैध घुसपैठिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हों, बल्कि नौकरियों और संसाधनों पर भी कब्जा जमा रहे हों। उत्तर प्रदेश- जो नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है और आठ राज्यों से घिरा है- अब ऐसे 'अनचाहे मेहमानों' के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'सूची, जांच, रिटर्न'- यानी एसआईआर- की रणनीति अपनाते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कस दिया है। 17 नगर निकायों में सफाईकर्मी-मजदूरों की स्कैनिंग, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, और लखनऊ की झुग्गियों में छापेमारी - यह सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का किलेबंदी है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश- 'अवैध घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता।' आइए, इस एक्सप्लेनर में समझते हैं - यह एक्शन क्या है, क्यों है, और कैसे चलेगा...

क्या है 'एसआईआर' रणनीति? योगी सरकार का तीन-चरणीय हथियार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों (DMs) को निर्देश दिए थे - अवैध घुसपैठियों की तत्काल पहचान करें, अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं, और कानूनी प्रक्रिया से निर्वासित करें। अब 3 दिसंबर को इसे और मजबूत किया गया:- 17 प्रमुख नगर निकायों (जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, गोरखपुर) में सफाईकर्मी, ठेके पर मजदूर या अन्य निम्न-स्तरीय नौकरियों में लगे रोहिंग्या-बांग्लादेशी मूल के लोगों की विस्तृत सूची तैयार करें। यह सूची संबंधित मंडलायुक्त और आईजी को सौंपी जाएगी, जो पहचान की गई महिलाओं/पुरुषों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करेंगे।

चरण 1: सूची - पहचान का फंडा

17 नगर निकायों में फील्ड सर्वे शुरू। सफाई विभाग, निर्माण स्थल, झुग्गी-झोपड़ियां - हर जगह दस्तावेज चेक। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र - सबकी सत्यापन। संदिग्ध दस्तावेजों की जांच संबंधित जिलों/थानों से। उद्देश्यः फर्जी आईडी से सरकारी लाभ (जैसे पेंशन, सब्सिडी) लेने वालों को बेनकाब करना।

चरण 2: जांच - सत्यापन का डंडा

पुलिस-प्रशासन संयुक्त टीमें गठित। सीमावर्ती जिलों (जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद) में विशेष फोकस, क्योंकि यहां घुसपैठ ज्यादा। नेपाल बॉर्डर से आने वाले बांग्लादेशी/रोहिंग्या को टारगेट। डिजिटल ट्रेसिंगः मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजेक्शन चेक।

चरण 3: रिटर्न - निर्वासन का अंतिम चरण

डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद कानूनी प्रक्रियाः पहचान साबित होने पर विदेश मंत्रालय के जरिए निर्वासन। योगी ने कहा, ' कानूनी तरीके से उनके देश भेजेंगे।' हर मंडल (18 मंडल) में एक-एक डिटेंशन सेंटर - पहले चरण में अस्थायी, बाद में स्थायी।

यह रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, क्योंकि वढ की भौगोलिक स्थिति (नेपाल के साथ 599 किमी खुली सीमा) घुसपैठ को आसान बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट का साथः ' लाल कालीन नहीं, कानून का राज'

2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। उखक जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहाः ' अवैध घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। भारत पर उन्हें रखने का कोई दायित्व नहीं।' उन्होंने गृह मंत्रालय के 'शरणार्थी' घोषणा आदेश की मांग की। याचिकाकताओं के वकील ने तर्क दिया - निर्वासन का विरोध नहीं, लेकिन हिरासत में 'गायब' होने का डर। ' उचित प्रक्रिया और लिखित आदेश जरूरी।' लेकिन उखक ने पलटकर पूछाः ' क्या घुसपैठ के बाद सभी अधिकार मिल जाते हैं?' मामला जनवरी 2026 के लिए स्थगित। यह फैसला योगी सरकार के अभियान को मजबूती देता है - मानवाधिकारों का हवाला देकर घुसपैठ को वैध नहीं ठहराया जा सकता।

ग्राउंड एक्शनः झुग्गियों पर छापा, सैकड़ों दस्तावेज जब्त

निदेर्शों पर अमला एक्शन में। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में बांग्लादेशी महिला नरगिस के पकड़े जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने ऊढ दक्षिण को विशेष अभियान सौंपा। बिजनौर थाना के न्यू गड़ौरा और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल वाली झुग्गियों में छापेमारी। सैकड़ों आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड चेक। संदिग्ध दस्तावेजों की सत्यापन संबंधित जिलों से। एक अधिकारी ने बताया, ' कई फर्जी पाए गए, जिनकी डिटेल्स मंडलायुक्त को भेजी जा रही।'

इसी तरह, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में सर्वे शुरू।

क्र. शहर/निकाय कार्रवाई का फोकस अपेक्षित आउटकम

1 लखनऊ झुग्गी छापेमारी, दस्तावेज सत्यापन 100+ संदिग्ध पहचान

2 कानपुर सफाईकर्मी स्कैनिंग सूची कमिश्नर को

3 वाराणसी सीमा क्षेत्र सर्वे डिटेंशन सेंटर सेटअप

4 नोएडा-गाजियाबाद निर्माण स्थल जांच फर्जी आईडी जब्त

क्यों जरूरी है यह अभियान? घुसपैठ की सच्चाई और खतरे

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या (म्यांमार से भागे मुस्लिम समुदाय) और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या हजारों में। वे फर्जी दस्तावेजों से वोटर बन, सब्सिडी ले, और नौकरियां छीन रहे। खतरेः सुरक्षा जोखिमः जासूसी, आतंक लिंक की आशंका।

संसाधन दबावः घनी आबादी वाले शहरों (लखनऊ, नोएडा) में बुनियादी सुविधाओं पर बोझ।

सामाजिक असंतुलनः स्थानीय रोजगार प्रभावित, चुनावी सूची में घुसपैठ।

सरकार का तर्कः ' ये लोग कानून तोड़कर आए, उन्हें लाभ नहीं।' पिछले वर्षों में वढ ने 500+ घुसपैठियों को निर्वासित किया। अब लक्ष्यः शून्य सहिष्णुता। आगे क्या? चुनौतियां और उम्मीदेंए अभियान तेज, लेकिन चुनौतियांः मानवाधिकार संगठनों का विरोध, फर्जी दस्तावेजों की भरमार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का समर्थन और केंद्र की 'नागरिकता संशोधन' नीति से मजबूती। जनवरी तक पहली लिस्ट तैयार, डिटेंशन सेंटर चालू।

### प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार साझा किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लिंक्डइन पोस्ट पर अपने लिखे एक आर्टिकल में प्राकृतिक खेती पर अपने विचार शेयर किए। श्री मोदी ने कहा, "दो हफ्ते पहले, मैं कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर एक समिट में था, जिसने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी।

इस लिंक्डइन पोस्ट में इस पर कुछ विचार बताए, साथ ही पूरे भारत के लोगों से प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की अपील की। एक नजर डालें।"

प्रधानमंत्री ने पर पोस्ट किया:

"दो हफ्ते पहले, मैं कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर एक समिट में था, जिसने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी।

## पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावः पीएम ने सांसदों को दिया 'मोदी मंत्र'; कहा- जीतना है... ममता सरकार को काउंटर करें

कोलकाता (जीएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आक्रामक तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार को काउंटर करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के बीच जाना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को साफ संदेश देते हुए कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखें और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने सांसदों को राज्य की स्थिति पर आक्रामक रुख अपनाने और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर जनता के बीच और मजबूती से उतरने को कहा।

नई दिल्ली में बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगन मुर्मू भी मौजूद रहे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला किया था। प्रधानमंत्री ने उनकी कुशलक्षेम पूछी और बाकी सांसदों से कहा कि उन्हें राज्य की तृणमूल सरकार का मजबूती से मुकाबला करना होगा ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया जा सके। भाजपा नेताओं के अनुसार, मोदी ने साफ कहा कि चुनाव जीतना है और जीतेंगे।

पीएम ने लड़ाई जारी रखने को कहा

बैठक के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं को कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाए और जनता के बीच लगातार पहुंच बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं ताकि अगले साल टीएमसी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके।

## पंजाब आप सरकार की बड़ी पहल, नशा विरुद्ध अभियान में नियुक्त होंगे मेंटल हैल्थ फैलो, 60 हजार रुपये महीना सैलरी

(जीएनएस)।

पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरूआत हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश की पहली सरकारी लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करके साफ कर दिया है कि "युद्ध नशे विरुद्ध" सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक जमीनी लड़ाई है, जिसमें हर परिवार की सुरक्षा और भविष्य दांव पर है। यह फेलोशिप 2 साल की होगी। जिसमें न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनने जा रही है।

एम्स मोहाली और टीआईएसएस मुंबई की साझेदारी में शुरू हुई यह पहल 23 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य और नशा-निवारण को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगी। सरकार 35 ऐसे युवा विशेषज्ञ चुन रही है जो साइकोलॉजी या सोशल वर्क की पढ़ाई कर चुके हैं और जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य में काम करने का अनुभव है।

ये फेलो पंजाब के गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर और

रिहैब सुविधाओं तक पहुँचकर एक ऐसे मॉडल को लागू करेंगे जिसकी कल्पना भारत ने पहले नहीं की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास तीनों को एक साथ जोड़कर।

भगवंत मान की सोच यह मानती है कि नशे से लड़ाई सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के मन को मजबूत करने की जरूरत है। इसी सोच के कारण इस कार्यक्रम में फेलोज को टीआईएसएस मुंबई से विशेष ट्रेनिंग, मेंटरशिप और जमीनी नेतृत्व सीखने का मौका मिलेगा। उन्हें 60,000 रुपये महीना का सम्मानजनक रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, ताकि वे बिना किसी दबाव के पूरी ऊर्जा से पंजाब के युवाओं और परिवारों के साथ काम कर सकें।

यह कार्यक्रम असल मायने में पंजाब के दिल की धड़कन है। नशा एक महामारी की तरह फैल चुका था, लेकिन अब पंजाब ने यह लड़ाई विशेषज्ञों के साथ मिलकर, वैज्ञानिक तरीकों से और लोगों के बीच उतरकर लड़ने का फैसला लिया है। भगवंत मान ने दिखा दिया है कि जब नीयत साफ हो और लक्ष्य जनता की भलाई हो, तो सरकारें बदलाव लेकर आती हैं, बयान नहीं।

### परमाणु संयंत्रों को चालू करने में देरी

राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना, RAPP-8 (700 मेगावाट) के पूरा होने/चालू होने में देरी हो गई है। इसका कारण मुख्य रूप से जापान में फुकुशिमा दुर्घटना के गहन विश्लेषण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर डिजाइन की समीक्षा और नए अपग्रेड को शामिल करना है। एक और परियोजना, कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना, KKNPP-3 और 4 (2 1000 मेगावाट) में रूस-यूक्रेन के बीच वर्तमान विवाद और ज़िला प्रशासन द्वारा खदान का काम रोकने के कारण रॉक प्रोडक्ट्स की अनुपलब्धता के कारण देरी हुई है। इसके अलावा, ठेकेदारों की पैसे की तंगी और कोविड 19 महामारी के असर से भी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई। तमिलनाडु के कलपक्कम में बीएचएवीआईएनआई द्वारा शुरू किए जा रहे 500 टही प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और चालू करने के चरण में देरी हुई।

## पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भुज के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 03 दिसम्बर, 2025

यात्रियों की सुविधा के लिए तथा अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस – भुज स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर पूर्ण आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09037/09038 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट (द्विसाप्ताहिक) स्पेशल [24 फेरे]

ट्रेन संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:50 बजे भुज पहुंचेगी। यह ट्रेन 06 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09038 भुज – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को भुज से 17:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 दिसम्बर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर ठहरेगी।

यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित रहेगी तथा इस ट्रेन में एसी 3-टियर कोचेस रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09037 एवं 09038 की बुकिंग 04 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

## एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण

- डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया कि एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की इसरो की अच्छी तैयारी दशार्ता है
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसरो के सफल अत्यंत दुर्गम स्थिति पैराशूट परीक्षण ने गगनयान के लिए सुदृढ़ मिशन सुरक्षा मानक स्थापित किए
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद को आश्वस्त किया: सभी परीक्षण परिणाम अंतरिक्ष यात्रियों की आपातकालीन स्थिति और बचाव प्रशिक्षण में शामिल किए जाएंगे
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने अत्यंत दुर्गम स्थिति में सफल पैराशूट परीक्षण के बाद संसद को बताया कि 2027 की पहली तिमाही में भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज संसद को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो द्वारा हाल में एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, के लिए मिशन-तैयारी योजना को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह परीक्षण, अंतरिक्ष यान चालक दल के पैराशूट-आधारित मंदन प्रणाली के योग्यता अभियान का महत्वपूर्ण घटक है, जो इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

डॉ. सिंह ने बताया कि नवीनतम एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप में सबसे चरम अवतरण स्थितियों में से एक का अनुकरण किया गया और दो मुख्य पैराशूटों के बीच डिसरीफिंग क्रम में जानबूझकर समय का अंतर रखा गया। इसमें असममित बलों के तहत प्रणाली की संरचनात्मक जुड़ाव और भार वहन क्षमता, दोनों की पुष्टि हुई। श्री सिंह ने कहा कि यह सफल परीक्षण मानव-योग्यता निर्धारण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है और 2027 की पहली तिमाही तक पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन प्रक्षेपित करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।

संसद में प्रश्नकाल के दौरान तृतीय-पक्ष सत्यापन और तकनीकी निगरानी पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि इसरो नियमित रूप से क्रू मॉड्यूल पैराशूट प्रणाली और उससे संबंधित सभी परीक्षण परिणामों की स्वतंत्र और कठोर समीक्षा करता है। इनमें डिजाइन समीक्षा दल, स्वतंत्र मूल्यांकन समिति और मानव योग्यता निर्धारण एवं प्रमाणन के लिए देश भर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये संस्थागत मंच सभी मानव-मूल्यांकन तत्वों की गहन जांच करते हैं।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों पर श्री सिंह ने कहा कि इसरो निरंतर और समय-समय पर प्रमुख परीक्षण परिणामों की जानकारी देता रहता है, जिसमें हाल ही किये गए आई.एम.ए.टी. के परिणाम भी शामिल हैं। वह आगे भी कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सूचित करना जारी रखेगा।

यान चालक दल की तैयारियों से संबंधित मुददों पर, डॉ. सिंह ने दोहराया कि गगनयान मिशन के लिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रणालियों का गहन परीक्षण और विशेषज्ञ समीक्षा की जाती है, और प्रत्येक योग्यता परीक्षण के परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर प्रणाली में सुधार किया जाता है। इसके बाद फिर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में आपातकालीन परिदृश्यों का व्यापक अनुकरण, ऑफ-नॉमिनल लैंडिंग की उत्तरजीविता प्रक्रियाएं, आपातकालीन किट का संचालन और गगनयात्रियों की समग्र तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल है।

श्री सिंह ने सदन को यह भी बताया कि इसरो ने स्थापित वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ जोखिम-मूल्यांकन और न्यूनीकरण ढांचे को संस्थागत रूप दिया है। मानव मूल्यांकन प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय सलाहकार पैनल जैसी संस्थाएं इन प्रक्रियाओं की निगरानी करती हैं ताकि सुनिश्चित हो कि समग्र मिशन के दौरान जोखिम नियंत्रण में रहे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि हाल के आईएमएटी सहित प्रत्येक परीक्षण का महत्वपूर्ण प्रणालियों को मान्य बनाने के साथ ही चालक दल के प्रशिक्षण, ग्राउंड रिकवरी तैयारियों और भारत के ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सुरक्षित निष्पादन में योगदान है।

## विभिन्न सेक्टरों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

(जीएनएस)।

भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में, विकसित किए गए प्रमुख अनुप्रयोगों में प्रमुख फसलों के लिए कटाई-पूर्व क्षेत्रफल और उत्पादन अनुमान, बागवानी फसलों का मानचित्रण और मूल्यांकन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खरीफ के बाद चावल के परती क्षेत्रों के इष्टतम उपयोग के लिए फसल गहनता, सूखा निगरानी और प्रबंधन, पीएमएफबीवाई योजना के तहत फसल उपज अनुमान आदि शामिल हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) की स्थापना के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रचालनगत है।

इसी प्रकार, उपग्रह डेटा का उपयोग विभिन्न आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन, भूकंप, जीएलओएफ और कृषि सूखे के लिए आपदा प्रबंधन सहायता के लिए किया जाता है। भारतीय उपग्रहों जैसे, इनसैट-3डीआर और 3डीएस और ईओएस-06 का डेटा उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी के लिए और चक्रवाती तूफान, ट्रैक, तीव्रता के साथ-साथ भूस्खलन के समय और स्थान की पूर्व चेतावनी देने के लिए आईएमडी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसरो बाढ़ (नदी या चक्रवाती) के दौरान बहु-सेंसर उपग्रह डेटा से प्राप्त बाढ़ के जलप्लावन मानचित्र संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन सहायता के लिए प्रदान करता है। बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण (छह प्रमुख बाढ़ संभावित राज्यों के लिए) और स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल (गोदावरी और तापी बेसिन के लिए) भी विकसित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इसरो ने हिमालय में ग्लेशियल झीलों (>0.25 हेक्टेअर क्षेत्र) की मैपिंग और 15 प्राथमिकता वाली ग्लेशियल झीलों की जीएलओएफ रिस्क मॉडलिंग भी की है। इसरो, वन अग्नि मौसम के दौरान, प्रतिदिन छह से आठ बार, वन अग्नि प्रबंधन हेतु एफएसआई/पृथ्वी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों को सक्रिय वन अग्नि की जानकारी प्रसारित करता है। प्रमुख वन अग्नि के लिए वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण भी किया जाता है। इसरो भूस्खलन की उपग्रह डेटा-आधारित सूची तैयार करता है और भूस्खलन तथा भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन करता है। ड्रॉट मैन्युअल 2020 के अनुसार, नेशनल जियोस्पेशियल ड्रॉट पोर्टल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, एसएसी/इसरो के वेदास जियोपोर्टल पर विकसित किया गया है। यह तालुका और जिला स्तर पर विभिन्न माध्यमों से सूखे का पाक्षिक मूल्यांकन प्रदान करता है।

शहरी मास्टर प्लान की तैयारी में संभावित उपयोग के लिए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) परियोजना के अंतर्गत शहरी भू-स्थानिक डाटाबेस के निर्माण के लिए अति उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, इसरो कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी/अनुप्रयोग प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

## भारत के टुकड़ों का मनसूबा पालने वाला अब्दुल्लाहिल अमान आजमी कौन है? ना-पाक इरादे असीम मुनीर जैसे!

(जीएनएस)।

'जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक बांग्लादेश में पूरी शांति नहीं आएगी।' यह जहर भरी बातें कोई फुटपाथ पर चिल्लाता उन्मादी नहीं उगल रहा, बल्कि बांग्लादेश आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी है। जमात-ए-इस्लामी के विवादास्पद पूर्व प्रमुख गुलाम आजम के बेटे ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में खुल्लमखुल्ला भारत को निशाना बनाते हुए यह बयान दिया। आजमी की यह बौखलाहट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर (अꣳ टჯल्ल१) की 'इ ीींकिल्ल्र्ा ह्व३ँ ळॅंङ्क४रंल्ल्रा उ४३२' वाली नापाक रणनीति से एकदम मेल खाती है- दोनों का मकसद भारत की एकजुटता को चूर-चूर करना।

शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में फल-फूलते कट्टरपंथियों का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत घृणा नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क की अस्थिरता को भारत पर लादने की साजिश का आईना है। लेकिन क्या आजमी का यह 'विखंडन का सपना' भारत की अटूट एकता को हिला सकता है? आइए खोलते हैं आजमी की परतें – कौन हैं वे, उनका काला इतिहास क्या है, बयान का संदर्भ क्यों खतरनाक, और भारत को कैसे दिखानी चाहिए बांग्लादेश को उसकी हद। याद रखिए, 1971 में भारत ने

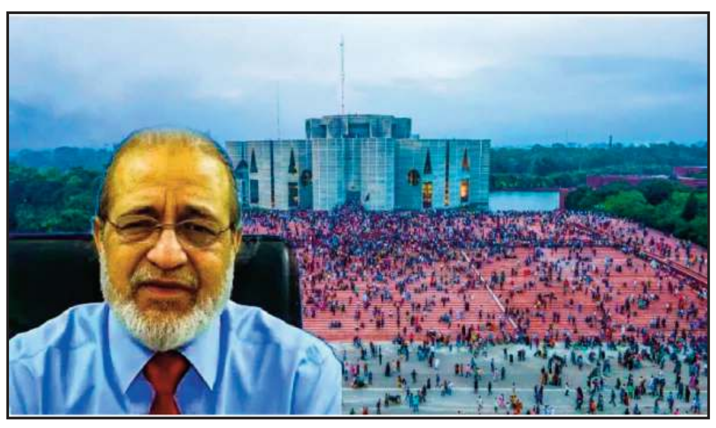

बांग्लादेश को पाकिस्तानी जंजीरों से आजाद कराया था – अब वक्त है 'कृतज्ञता' की सीख दिलाने का, वरना इतिहास खुद दोहराएगा...

ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अब्दुल्लाहिल अमान आजमी कोई साधारण पूर्व सैनिक नहीं- वे बांग्लादेश के विवादास्पद चेहरे हैं, जिनकी जिंदगी राजनीतिक घृणा और कट्टरवाद से बुनी गई है। 1958 में ढाका में जन्मे आजमी, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के उस दौर में पले-बढ़े जब उनके पिता गुलाम आजम जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख थे। गुलाम आजम पर 1971 की मुक्ति संग्राम के दौरान हिंदुओं और बंगाली मुक्ति समर्थकों के नरसंहार का आरोप लगा- वे पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। आजम को 2013 में युद्ध अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा हुई, और 2014 में जेल में उनकी मौत हो गई।

आजमी ने नोट्र डेम कॉलेज से हाई स्कूल किया, फिर बांग्लादेश आर्मी जॉइन की। 2009 में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पहुंचे, लेकिन शेख हसीना सरकार ने उन्हें पेंशन के बिना बर्खास्त कर दिया- कारण? भारत-विरोधी बयानबाजी। 2016 में वे जबरन गायब हो गए- आठ साल तक 'अयनाघर' नामक गुप्त डिटेंशन सेंटर में कैद रहे। अगस्त 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने दावा किया,'मैं भारत-विरोधी पोस्ट के कारण गायब हुआ।' दिसंबर 2024 में उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर 'अनचाही रिटायरमेंट' में बदल दिया गया।

आजमी का भारत-विरोध पुराना है। सोशल मीडिया पर वे अक्सर भारत को 'क्षेत्रीय आक्रामक' बताते हैं। 2015 में उन्होंने 1971 युद्ध में भारतीय सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय गान और संविधान बदलने की मांग की – ताकि 'इस्लाम-विरोधी' कानून न बने। जमात ने साफ कहा: 'आजमी हमारे सदस्य नहीं, उनके बयान निजी हैं।' लेकिन उनकी विरासत? पिता की तरह कट्टरवाद का प्रतीक।

बयान का पूरा संदर्भ: ढाका प्रेस क्लब में जहर, चटगांव का पुराना घाव खोदा

2 दिसंबर 2025 को ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में एक इवेंट के दौरान आजमी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ जहर उगला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा:- 'जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक बांग्लादेश में पूरी शांति नहीं होगी। भारत हमेशा बांग्लादेश में अशांति फैलाता रहता है।' उन्होंने 1975-1996 के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (उऌळ) संघर्ष को निशाना बनाया। कहा- 'शेख मुजीबुर रहमान के समय ढउखरर (पर्वतीय चटगांव जन संहति समिति) बनी, जिसकी आर्म्ड विंग शांति बाहिनी थी। भारत ने उन्हें शरण, हथियार और

## जल संसाधन विभाग में एक सहायक अभियंता सहित अनुकम्पा पर नियुक्त 32 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए

पटना में जल संसाधन विभाग ने अनुकंपा के आधार पर चयनित 32 कर्मचारियों, जिनमें एक सहायक अभियंता भी शामिल थे, को नियुक्ति पत्र जारी किए। समारोह में विभागीय दक्षता और मृत कर्मचारियों के परिवारों का सम्मान करने पर जोर दिया गया, ईमानदारी, तत्परता और सेवा पर टिप्पणी की गई।

(जीएनएस)।

पटना स्थित सिंचाई भवन के सभागार में आज जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक नवनियुक्त सहायक अभियंता तथा अनुकम्पा के आधार पर चयनित 32 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का

शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद अपर सचिव के. डी. प्रौज्वल ने सभी अधिकारियों एवं नवनियुक्त कर्मियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सहायक अभियंता सहित सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हुई है, जो विभाग की दक्षता और संवेदनशीलता को दशार्ती है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "आज आप जल संसाधन विभाग से जुड़ रहे हैं। यह केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि अपनी क्षमता साबित करने का अवसर है। अपेक्षा है कि सभी कर्मी ईमानदारी, तत्परता और समर्पण के साथ दायित्व निभाएँगे और विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाएँगे। विभाग ने आप पर भरोसा जताया है, इसलिए अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी आपकी जिम्मेदारी है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नियुक्ति संबंधी मामलों के निष्पादन में विभाग ने गति लाई है, जो सराहनीय है।

विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने भी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन सभी के जीवन में नई शुरूआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 32 कर्मियों के असामयिक निधन के बाद उनके परिजनों को जो अवसर मिला है, वह बड़ी जिम्मेदारी है।

## इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइटें हुई कैंसिल, मुंबई से बेंगलुरू तक मचा हाहाकार, आखिर क्या है वजह?

(जीएनएस)।

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ समय से अपनी खामियों के कारण पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई है। हर दिन 2,200 से अधिक उड़ानें" संचालित करने वाली इंडिगो एयरलाइन ने 3 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत अन्‍य शहरों की लगभग 200 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 दिसंबर को उस समय भारी अफरा-तफरी देखने को मिली, जब इंडिगो की कई उड़ानें गंभीर देरी और रद्द होने से प्रभावित हुईं। ऐसा माहौल केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुईं और यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी

आखिर क्यों रद्द की गई इंडिगो की 200 फ्लाइट?

इसके पीछे मुख्य कारण पिछले

महीने लागू हुए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL)' के संशोधित नियमों के बाद क्रू मेंबर्स और खासकर पायलटों की भारी कमी है। नए नियमों में अधिक आराम के घंटे और मानवीय रोस्टर अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन इंडिगो को अपने विशाल नेटवर्क को इनके अनुरूप ढालने में संघर्ष करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स और पायलट की कमी के चलते ये उड़ाने रद्द करनी पड़ी।

क्या है नियम?

बता दें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम क्रू मेंबर्स के ड्यूटी पर रहने के घंटों को सीमित करते हैं। वे प्रतिदिन आठ घंटे, प्रति सप्ताह 35 घंटे, प्रति माह 125 घंटे और प्रति वर्ष 1,000 घंटे तक उड़ान को सीमित करते हैं। इस नियम का सख्ती से पालन होने के कारण इंडिगो बड़े स्तर पर क्रू मेबर्स और पायलट की कमी को झेल रही है।

गौरतबल है कि इंडिगो का डोमेस्टिक उड़ानों में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा है, इसलिए इसका असर पूरे हवाई यात्रा तंत्र पर महसूस किया गया है। इंडिगो ने एक बयान में कहा, "हम स्वीकार करते हैं कि पिछले दो दिनों से इंडिगो के परिचालन में नेटवर्क भर में महत्वपूर्ण व्यवधान आया है, और हम अपने कस्‍ मर्स को हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं।"

एयरलाइन ने आगे कहा, "अनेक अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियाँ, जिनमें मामूली तकनीकी गड़बड़ियाँ, सर्दियों के मौसम से जुड़े कार्यक्रम परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमानन प्रणाली में बढ़ती भीड़ और चालक दल के रोस्टर नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) के अद्यतन कार्यान्वयन शामिल हैं, का हमारे परिचालन पर एक साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसकी पहले से उम्मीद करना संभव नहीं था।"

## इसरो ने पांच मॉड्यूल वाले स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पूरी आकृति तैयार कर ली

(जीएनएस)।

इसरो ने पांच मॉड्यूल वाले स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पूरी आकृति तैयार कर ली है। इसके 2035 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इसकी पूरी आकृति की समीक्षा एक राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति ने की है। सितंबर 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस-01) के पहले मॉड्यूल के विकास और प्रक्षेपण को मंजूरी दी थी। बीएएस-01 मॉड्यूल की समग्र प्रणाली इंजीनियरिंग और विभिन्न उप-प्रणालियों की प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियां अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं।

विभिन्न पूर्ववर्ती मिशनों, बीएएस-1 के विकास और प्रक्षेपण के लिए बजटीय आवंटन को गगनयान कार्यक्रम के संशोधित दायरे में शामिल किया गया है। इसे सितंबर, 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन के आधार पर पहले से स्वीकृत गगनयान कार्यक्रम में अतिरिक्त धनराशि के साथ बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पहले मॉड्यूल अर्थात बेस मॉड्यूल (बीएएस-01) का विकास और प्रक्षेपण 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा पांच मॉड्यूलों के साथ बीएएस का पूर्णतः परिचालन 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसरो, बीएएस-01 उप-प्रणालियों के डिजाइन में आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल कर रहा है ताकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की प्रदत्त प्रणालियों के साथ बीएएस-01 की अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ वर्तमान में कार्यरत सहयोग उपकरणों के माध्यम से, भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और विशिष्ट परीक्षण सुविधाओं के उपयोग हेतु समर्थन सहित सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी खोज की जा रही है।

गगनयान पहला मानवयुक्त प्रदर्शन मिशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) तक सुरक्षित मानव परिवहन और पृथ्वी पर वापसी की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगला तार्किक कदम है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के और नए रास्ते खोलेगा, जिससे एलईओ में अद्वितीय सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण वातावरण का उपयोग उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों के लिए संभव होगा। साथ ही, इससे भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 में परिकल्पित भारतीय मानव अन्वेषण मिशनों (अर्थात, चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग) को भी सहायता मिलेगी।

## भारत का प्रवेश द्वार जहां से अंग्रेज भागे थे, दिलचस्प है इस जगह का इतिहास

(जीएनएस)।

मुंबई की पहचान बन चुका गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ एक स्मारक भर नहीं है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह जगह मुंबई शहर की पहचान है और इसे मायानगरी का लैंडमार्क भी कहा जाता है। मुंबई आने वाले पर्यटक भी इस जगह पर जरूर घूमने आते हैं। यह इमारत भारत के उपनिवेशकाल और आजादी के सफर का साक्षी भी है। अरब सागर के किनारे खड़ा यह शानदार मेहराबदार ढांचा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है।

गेटवे ऑफ इंडिया की कहानी 110 साल पहले शुरू होती है। यह इमारत एक शाही यात्रा की याद में बनाया गया था। एक दौर में यह भारत के औपनिवेशिक अतीत का साक्षी बना। भारत की आजादी के स्वर्णिम इतिहास का भी गवाह यही जगह बनी थी।

इतिहास है दिलचस्प

– ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी पहली बार दिसंबर 1911 में भारत आए थे। इस जोड़े की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक भव्य स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया था।

– इस वास्तुकला में मध्यकालीन गुजराती कला, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य की विशेषताओं का मेल दिखता है। विशाल मेहराब, जटिल नक्काशी और प्रभावशाली ढांचा इसे मुंबई का ताज बनाते हैं।

– इस प्रतिष्ठित संरचना का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने तैयार किया, जिन्होंने इसे इंडो-सारासेनिक शैली में तैयार किया।

9 साल में तैयार हुआ भारत का प्रवेश द्वार

गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1913 को रखी गई थी। हालांकि, प्रथम विश्व युद्ध और अन्य औपचारिकताओं के कारण निर्माण कार्य 1915 में शुरू हो पाया था। लगभग 9 साल की मेहनत के बाद यह स्मारक 1924 में पूरा हुआ। इसकी कुल निर्माण लागत उस समय करीब ₹21 लाख थी, जो उस दौर की एक बड़ी राशि मानी जाती थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्रिटिश सम्राट के आगमन के प्रतीक के तौर पर इसे बनाया गया था। आजादी के बाद एक ऐतिहासिक विदाई स्थल भी यही जगह साबित हुई थी। 1948 में यही वह जगह था, जहां से आखिरी ब्रिटिश सैनिक भारत छोड़कर गए।

आज गेटवे ऑफ इंडिया भारतीय ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी पसंदीदा स्थान है। यहां पास में ही ताज होटल है, जो भारत की भव्यता की कहानी कहता है। हर साल न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे मौकों पर यहां भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

# सम्पादकीय

## श्रीलंका की सहायता करने के दौरान भी पाक ने चली कुटिल चाल

श्रीलंका इस वक्त दैवी आपदा से जूझ रहा है। दुनिया के जो देश उसे राहत सामग्री भेज रहे हैं, उनमें श्रीलंका के लोगों के प्राति भ्रातृत्व भावना और मानवीय संवेदना का भाव दिखता है। 28 नवम्बर को दित्वा चव्रवात ने ऐसी तबाही लाईं कि श्रीलंका में 132 लोगों को काल ने लील लिया जबकि 176 लोग आज भी लापता हैं। अधिवृत आंकड़ों के मुताबिक 78000 लोग इस द्वीप राष्ट्र में आए भूस्खलन से हिल चुके हैं। श्रीलंका की इस दयनीय स्थिति से द्रवित मित्र भारत ने "ऑपरेशन सागर बंधु" चलाकर 53 टन राहत सामग्री हवाई और समुद्री मार्ग से भेजी। 2000 को स्वदेश वापस लाया गया। भारत से भेजी गईं एनडीआरएफ की टीम ने 200 से ज्यादा लोगों की जानें बचाईं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार जो लोग श्रीलंका में आईं आपदा में बचाए गए उनमें श्रीलंका, भारत, जर्मनी, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, दक्षिण अप्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं।

भारत कोलम्बो स्थित उच्चायोग, नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय और श्रीलंका के अधिकारियों से समन्वय बनाकर भारत ने 2 पोत आईएनएस विव्रंत और आईएनएस फिगेट उदयगिरी के जरिए 9.5 टन राशन तत्काल उपलब्ध कराया। यही नहीं भारत ने 13.5 टन राहत सामग्री, दो सचल अस्पताल 'भीष्म क्यूब' सुखना भारतीय नौसेना ने 12 टन राहत सामग्री भेजी। इस तरह वुल 53 टन सामग्री भारत ने श्रीलंका के पीड़ितों की मदद के लिए भेजी। श्रीलंका की सरकार और जनता दोनों भारत के प्राति आभार व्यक्त कर चुके हैं और दिल से आभार महसूस करते भी हैं। किन्तु पाकिस्तान ने एक्सपायरी डेट की राहत सामग्री भेजकर न सिर्प श्रीलंका की सरकार और पीड़ित जनता को चिढ़ाया बल्कि उनके कटे पर नमक छिड़का है, इससे दोनों देशों के बीच जो वूटनीतिक संवाद हुए उससे तो यही लगता है श्रीलंका इस्लामाबाद से उसके व्यवहार को लेकर अत्याधिक नाराज है जबकि पाकिस्तान पर कोई असर ही नहीं दिखता। मंगलवार को एक जानकारी के मुताबिक इस वूटनीतिक वार्ता के आदान-प्रादान का व्रम तो खत्म हो गया। असल में हुआ यह कि श्रीलंका में चव्रवात के तुरन्त बाद भारत की सव्रियता की प्रातिव्रिया पाकिस्तान पर भी हुईं। पाकिस्तान नेवी ने 29 नवम्बर को दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा किट, सूखा राशन, तम्बू और अन्य आवश्यक वस्तुएं श्रीलंका के कोलम्बो बंदरगाह पर भेजी। 30 नवम्बर को एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कोलंबो स्थित पाक उच्चायोग ने लिखा "पाकिस्तान से राहत पैकेट सफलतापूर्वक श्रीलंका के बाढ़ प्राभावित भाइयोंबहनों तक पहुंचाए गए। यह हमारी अटूट एकजुटता का प्रातीक है। पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है।" लेकिन जब श्रीलंका के अधिकारियों ने राहत सामग्री की जांच की तो पाया कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ भद्दा मजाक किया है। उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने वुटिलतावश या असावधानीवश दवाएं एवं खाने-पीने की सामग्री 2024 की एक्सपायरी डेट की भेज दी। तम्बू भी फटे-पुराने इससे पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि 2015 में उन्होंने भारत की नकल कर नेपाल भूवंप पीड़ितों को खाने-पीने की जो राहत सामग्री के तौर में भेजी वह बीफ मिश्रित थी। उस वक्त नेपाल ने काठमांडू स्थित पाक दूतावास के राजनयिकों को खरी खोटी सुनाईं थी और कहा था कि पाकिस्तान की सांस्वृतिक संवेदनहीनता से समूचा नेपाल आहत है। असल में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खंडित चिन्तन का शिकार हो चुका है। मतलब यह कि सरकार की सेना की जी हजूरी करते बीतती है इसलिए यह कहना ठीक होगा कि सरकार का कोईं दृढ़ विचार है ही नहीं या तो यह कहें कि उसकी कोईं वैचारिक पहचान ही नहीं है। उस पर सेना का दबाव होता है, इसलिए वह सेना के निदेर्शों के अनुसार ही विचार भी बनाती है और व्यवहार भी करती है। रही बात पाक सेना और आम जनता की तो जनता इस वक्त सेना के अनुसार नहीं सोचती। सेना ने वुछ पत्रकारों को खरीद रखा है जो उसके पक्ष में विमर्श जरूर बनाते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के वुछ शीर्ष सेवा से निवृत्त सैन्य एवं प्राशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अपने पक्ष और उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ माहौल बनाती है जो उसकी बातें नहीं मानती। लब्बोलुआब यह है कि पाकिस्तान जिस तरह मानवता के प्राति व्रूर मजाक करता है, उससे उसके शासकों यानि सेना और उसकी सरकार के प्राति वितृष्णा पैदा होती है। अब तो पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और वहां की आम जनता पर वेदना होती है जो आज भी सेना की गुलामी से त्रस्त हैं और उनके द्वारा चुनी सरकार को उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं।

# जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके एवं रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित गुजरात के निर्माण में जोड़ने की सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट

-: छठी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें :-

- भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुनिश्चित समयसीमा
- संयुक्त भर्ती तथा कॉमन सेंट्रल टेस्ट (सीईटी)
- हर दो वर्ष में निश्चित रिक्विजिशन विंडो
- संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन
- कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड
- रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो
- भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि-पुनर्गठन
- कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग
- 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

गांधीनगर,03 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके तथा रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित राष्ट्र-विकसित राज्य के निर्माण में जोड़ने के दिए गए विचार को राज्य में साकार करने का दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री पटेल ने इस उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रशासनिक ढाँचे तथा कार्य पद्धति में आवश्यक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है।

इस प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को अपनी छठी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी। जीएआरसी इससे पहले तक राज्य सरकार को पाँच रिपोर्ट सौंप चुका है।

मुख्यमंत्री को बुधवार को सौंपी गई जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी, टेक्नोलॉजी से युक्त तथा युवा केन्द्रित बनाने की लगभग 9 सिफारिशें की गई हैं।

जीएआरसी की इस छठी रिपोर्ट में जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, उनके अनुसार

1. भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए निश्चित टाइमलाइन

जिस भर्ती प्रक्रिया में तीन स्टेज हों, वह 9 से 12 महीने में और जिसमें दो स्टेज हों, वह 6 से 9 महीने में पूरी करने और भविष्य में इस समयावधि से भी कम समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो; ऐसी सिफारिश की गई है।

2. संयुक्त भर्ती तथा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी)

रिपोर्ट में समान शैक्षणिक योग्यता वाले विभिन्न कैडरों के लिए संयुक्त प्रिलिम्स तथा विषयवार मेन्स परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने की सिफारिश की गई है। इससे समान प्रकार के कैडर के लिए अलग-अलग परीक्षा पर होने वाले प्रशासनिक एवं वित्तीय खर्च में काफी कमी लाकर भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सकेगी।

3. हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो

हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो निर्धारित कर सभी विभागों द्वारा ऑनलाइन मांगपत्र सबमिट करने की व्यवस्था के साथ भर्ती नियमों, परीक्षा नियमों और प्रशिक्षण नियमों के लिए एक केन्द्रीय सेल का गठन करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके फलस्वरूप; भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक नियमों को बहुत तेजी से अंतिम रूप दिया जा सकेगा और भर्ती प्रक्रिया तेज बनेगी।

4. संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन (आईएएसएस)

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हाल में होने वाली मैनुअल जाँच के स्थान पर संपूर्ण डिजिटल दस्तावेज से जाँच करने से तथा डिजी-लॉकर की तरह ही एपीआई-लिंक्ड डेटाबेस और यूनिक उम्मीदवार डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के गठन से भर्ती करने वाली संस्था और सरकारी विभागों के बीच उम्मीदवारों के दस्तावेज आसानी से भेजे जा सकेंगे और डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन भी बहुत प्रभावशाली बनेगा।

5. कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उम्मीदवार आधारित यूनिक आईडी पर एंड टु एंड डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसमें आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की समग्र प्रक्रिया को ट्रैक किए जाने सकने की व्यवस्था के साथ जिलेवार पोस्टिंग के लिए डिजिटल माध्यम से जिला चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

6. रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो

एकीकृत डिजिटल पोर्टल द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स (विभागों-एजेंसियों-उम्मीदवारों) के बीच सूचना का आदान-प्रदान संभव होगा और उम्मीदवारों को एक ही प्रकार के दस्तावेज बार-बार अलग-अलग भर्ती संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण के साथ एकरूपता की सिफारिश की गई है।

7. भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि तथा पुनर्गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती के लिए नए मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (एमएसआरबी) का गठन करने और जीएसएसएसबी, जीपीएसएसबी तथा जीपीआरबी को गुजरात लोक सेवा आयोग के समक्ष आवश्यक व आर्थिक स्वायत्तता देने की सिफारिश इस रिपोर्ट में हुई है।

8. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग

राज्य में जहाँ तक संभव हो, परीक्षाएँ कम्प्यूटर आधारित (कम्प्यूटर बेस्ड) ली जाएँ और ऐसी परीक्षा की प्रभावी देखरेख के लिए हर भर्ती एजेंसी में एक अलग एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट (ईएमयू) की स्थापना की जाए। यह भी सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है।

9. 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

हर विभाग के लिए भावी आवश्यकताओं पर आधारित 10 वर्ष के भर्ती कैलेंडर की समीक्षा कर बहुत ही महत्वपूर्ण इमर्जेंसी सर्विस तथा क्रिटिकल कैडर की पहचान कर हर संभव तेजी से भर्ती करने की सिफारिश जीएआरसी ने की है।

देश के विकास में अग्रसर गुजरात के युवाओं को तेजी से अधिक एवं प्रभावी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प को इन सिफारिशों से पूरा किया जा सकेगा।

इतना ही नहीं; जीएआरसी द्वारा की गई ये सिफारिशें लागू करने से भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से कम समयसीमा में पूर्ण हो सके, राज्य के युवाओं को समय पर तथा पारदर्शी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लंबे समय से लंबित रिक्तियाँ तेजी से भरी जाएँ और सरकार की प्रशासनिक क्षमता एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में गति आए; ऐसा राज्य सरकार का दृष्टिकोण साकार होगा।

मुख्यमंत्री को जीएआरसी की यह छठी रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, प्रशासनिक सुधार प्रभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और जीएआरसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

जीएआरसी की छठी रिपोर्ट की सिफारिशें जीएआरसी की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर अपलोड की गई हैं।

# प्रदूषण ने छीन ली है चेहरे की चमक तो इन बातों का रखें ख्याल -शहनाज हुसैन

भारत में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या और अन्य कारणों से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।

देश में प्रदूषण का स्तर किसी से छिपा नहीं है। पिछले काफी हफ़्तों से ज्यादातर शहरों में पी एम लेवल 150 से पार रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कोलेजन और इलास्टिसिटी जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को नुकसान पहुंचाता है।

आज के समय में बढ़ते प्रदूषण का असर पर्यावरण के अतिरिक्त त्वचा और आंखों पर दिखाई देता है इसकी वजह से त्वचा बेजान और बेरुखी नजर आती हैं तथा त्वचा पर एक्ने, एक्जिमा व हाइपरपिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं जिससे आप समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं प्रदूषण के कारण त्वचा की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे त्वचा में नमी की कमी होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है।

मेरा यह सुझाव है कि बाहर से आते ही चेहरे को हल्के फेस वाश से जरूर धोएं ताकि त्वचा पर जमी धूल, गंदगी को हटाया जा सके जिससे त्वचा की सुरक्षा परत को सुरक्षित रखा जा सके

सनस्क्रीन का इस्तेमाल सूरज की यूवी किरणों के इलाबा प्रदूषण से भी आपकी स्किन की सुरक्षा करता है। एक व्यापक 30 एस पी एफ या उससे अधिक स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन का उपयोग करें।

सुबह बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं क्योंकि प्रदूषण और धूप मिलकर नुकसान को कई गुना बढ़ा देते हैं सप्ताह में दो से तीन बार स्किन की गहराई से सफाई और एक्सफोलिएशन करें ज्यादातर लोग त्वचा की सामान्य तरीके से क्लींजिंग करते हैं। जबकि बढ़ते प्रदूषण में स्किन को डीप क्लीनिंग करनी होती है। चेहरे को धोने के लिए ऑयल बेस्ड क्लींजर का यूज करें दिन में दो बार फेस वॉश जरूर करें पूरे दिन त्वचा पर प्रदूषण और गंदगी जमा हो जाती है जिसे साफ करने के लिए सोने से पहले डबल क्लींजिंग करें। इसमें पहले तेल आधारित क्लींजर से अशुद्धियों को पिघलाकर चेहरे को साफ किया जाता है।

इसके बाद पानी आधारित क्लींजर का इस्तेमाल किया जाता है जो रोमछिद्रों को साफ करता है। इसके बाद पेप्टाइड युक्त मरम्मत करने वाला सीरम लगाएं और मॉइस्चराइजर उपयोग करें।

बाहर जाते समय चेहरे को कपड़े से ढकें और धूल वाले स्थान से दूरी बनाएं आंखों के लिए चश्मा या धूप का चश्मा पहनें इससे धूल और धुएं का सीधा असर कम होता है त्वचा को डिटॉक्स और हाइड्रेट करने के लिए रोजाना पर्याप्त पानी जूस ,सूप पिएं और अपने भोजन में रोज फल व सब्जियां शामिल करें

इस दौरान एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेना भी मददगार साबित हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादातर फल और सब्जियों में पाए जाते हैं फलों में ज्यादातर जामुन , स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी , रास्पबेरी, अंगूर , संतरे और अनार में पाए जाते हैं सब्जियों में पालक , गाजर और ब्रॉक्ली इसके स्त्रोत हैं

प्रदूषण से जंग जीतने में घर से बाहर निकलने से पहले त्वचा पर विटामिन.सी युक्त सिरम जरूर लगाएं। इससे स्किन को फ्री रेडिकल से बचाया जा सकता है और त्वचा की रंगत में निखार आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त क्रीम लगाने से चेहरे के पिगमेंटेशन कम होते हैं और त्वचा को कई अन्य लाभ भी मिलते हैं।

इस दौरान ज्यादा गर्म या ठंडे पानी से नहाने से परहेज करें क्योंकि यह त्वचा को शुष्क बना सकता है इसकी बजाय सामान्य या गुनगुने पानी का इस्तेमाल बेहतर साबित होगा

बार बार मुंह धोने से त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर पड़ सकती है इसलिए दो बार से ज्यादा मुंह न धोएं अगर आपकी त्वचा में जलन हो रही हो तो कठोर स्क्रब, अल्कोहल.आधारित टोनर और रेटिनॉइड जैसे उत्पादों से परहेज करें क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं।

यदि आपकी त्वचा शुष्क है तो आपको क्लीजिंग क्रीम तथा जैल का प्रयोग करना चाहिए जबकि तैलीय त्वचा में क्लीनिंग दूध या फेस वाश का उपयोग किया जा सकता है। सौंदर्य पर प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए चन्दन, यूकेलिप्टस, पुदीना, नीम, तुलसी, घृतकुमारी जैसे पदार्थो का उपयोग कीजिए। इन पदार्थो में विषैले तत्वों से लड़ने की क्षमता तथा बलवर्धक गुणों की वजह से त्वचा में विषैले पदार्थो के जमाव तथा फोडे, फुन्सियों को साफ करने में मदद मिलती है। वायु प्रदूषण खोपड़ी पर भी जमा हो जाते है।

एक चम्मच सिरका तथा घृतकुमारी में एक अण्डे.को मिलाकर मिश्रण बना लीजिए तथा मिश्रण को हल्के-2 खोपड़ी पर लगा लीजिए। इस मिश्रण को खोपड़ी पर आधा घण्टा तक लगा रहने के बाद खोपड़ी को ताजे एवं साफ पानी से धो डालिए। आप वैकल्पिक तौर पर गर्म तेल की थैरापी भी दे सकते है। नारियल तेल को गर्म करके इसे सिर पर लगा लीजिए। अब गर्म पानी में एक तौलिया डुबोइए तथा तौलिए से गर्म पानी निचोडने के बाद तौलिए को सिर के चारों ओर पगड़ी की तरह बांध कर इसे पांच मिनट तक रहने दीजिए तथा इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराईए। इस प्रक्रिया से बालों तथा खोपड़ी पर तेल को सोखने में मदद मिलती है। इस तेल को पूरी रात सिर पर लगा रहने दें तथा सुबह ताजे ठंडे पानी से धो डालिए।

प्रदूषण से जंग में पानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस दौरान आप ताजे , स्वच्छ जल का अधिकतम उपयोग कीजिये क्योंकि पानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकलने तथा कोशिकाओं को पौष्टिक पदार्थों को बनाये रखने में मदद करता है प्रदूषण की वजह से त्वचा को हुए नुकसान की भरपाई पानी से आसानी से की जा सकती है

ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 फैटी एसिड त्वचा को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने में अहम भूमिका अदा करते है फैटी एसिड्स त्वचा में आयल शील्ड बना देते हैं जिससे त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से होने बाले नुकसान से सुरक्षा प्राप्त होती है

ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बफीर्ले पहाड़ों की नदियों में पाए जाने बाली मछली , अखरोट , राजमा , तथा पालक में प्रचूर मात्रा में मिलता है जबकि ओमेगा 6 चिकन ,मीट ,खाद्य तेलों ,अनाज तथा खाद्य बीजों में पाया जाता है

वायु में प्रदूषण तथा गंदगी से आंखों में जलन तथा लालिमा आ सकती है। आंखों को ताजे पानी से बार-2 धोना चाहिए। काटन वूल पैड को ठण्डे गुलाब जल या ग्रीन-टी में डुबोइए तथा इसे आँखों में आई पैड की तरह प्रयोग कीजिए। आंखों में आई पैड लगाने के बाद जमीन में गद्दे पर 15 मिनट तक आराम में शव आसन की मुद्रा में लेट जाइए। इससे आंखों में थकान मिटाने में मदद मिलती है तथा आंखों में चमक आती है।

वायु में प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए हम कुछ औषधीय पौधों को मदद भी प्राप्त कर सकते है। इन पौधों में एलोवेरा सबसे लाभदायक माना जाता है जो कि सामान्यतः सभी भारतीय घरों में आसानी से देखा जा सकताहै। यह घरों में ऑक्सीजन के प्रवाह को तेज करता है तथा प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है। यह कार्बनडायक्साईड तथा कार्बन मोनोआक्सीईड को सोख कर आक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है।

इसके अलावा अंजीर, बरगद, पीपल का वृक्ष और स्पाईडर प्लांट भी हवा को साफ करने में काफी सहायक माना जाता है क्योंकि यह हवा में विद्यमान जहरीले तत्वों को सोख लेते है। इसके अलावा सान्सेवीरिया जिसे सामान्य भाषा में स्नेक प्लांट कहा जाता है भी वायु प्रदूषण को रोकने तथा ताजा स्वच्छ वायु प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्नेक प्लांट को सामान्य बेडरूम में रखा जाता है तथा इसकी देखभाल भी काफी आसान तथा सामान्य है। इसके अलावा ऐरेका पाम, इंग्लिश आईवी, बोस्टन फर्न तथा पीस लिलो जैसे पौधे भी भारत में आसानी से मिल जाते है तथा पर्यावरण मित्र माने जाते है।

लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ हैं और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है

# 'तुम जवान हो, चिंता मत करो', रात 2 बजे बेटी के टूटने पर आंखें नम करने वाले पिता के बोल हुए वायरल

(जीएनएस)।

सोशल मीडिया पर टटर लीक कांड ने इस वक्त तहलका मचा रखा है। इस बीच, इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लेने वाला वीडियो सामने आया। इसमें एक पिता ने रात के 2 बजे अपनी बेटी को वो बातें कहीं, जिसके बाद बच्चों के मन में आवाज उठ रही है- 'काश हर पापा ऐसे होते...'

दरअसल, एक छोटा सा फोन कॉल, आंसुओं से भरी बेटी और पिता की वो शांत, गहरी आवाज - 'ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनोगे तभी कुछ होगा... तुम अभी जवान हो, दबाव मत लो बच्चे... मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं।' वीडियो को अब तक 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज, लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं। आइए जानते हैं किस बारे में हो रही थी बात?

रात के 2 बजे क्या हुआ था? वायरल वीडियो की पूरी कहानी

वीडियो में एक युवती (उम्र करीब 19-20 साल) कैमरे के सामने बैठी है। आंखें लाल, गालों पर आंसुओं की लकीरें। वो फोन पर अपने पापा से बात कर रही है। आवाज में घबराहट और थकान साफ झलक रही है। शायद करियर का प्रेशर, पढ़ाई का बोझ या सोसाइटी का डर - सब कुछ एक साथ टूट पड़ा था।

गर्ल ब्रेक डाउन

पिता की आवाज शांत, लेकिन इतनी मजबूत कि सुनने वाला भी सुकून महसूस करे। वो बार-बार कहते हैं:-

'ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनेंगे तभी कुछ होगा। भारत में और भी हजार रास्ते हैं।'

'तेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं हो गई है... दबाव मत डालो खुद पर, बच्चे।'

'पढ़ाई बंद कर दो अगर मन नहीं लग रहा। कई बार एक ही रूटीन से ऊब जाते हैं लोग - ये बिल्कुल नॉर्मल है।'

'तू बहुत होशियार बच्ची है। और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। चिंता मत करो।'

'तुम जवान हो... अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है।'

गर्ल ब्रेक डाउन

बस यही कुछ मिनटों की बातचीत। कोई लेक्चर नहीं, कोई डांट नहीं, कोई तुलना नहीं। सिर्फ बिना शर्त का प्यार और भरोसा। वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है:- 'जब मैं रात के 2 बजे पापा को फोन करती हूं, तो वो हमेशा मुझे हौसला देने के लिए तैयार रहते हैं।'

सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई भावनाओं की

वीडियो जैसे ही एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पहुंचा, लोग अपने-अपने पापा को टैग करने लगे। कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो दिल छू गए:-

गर्ल ब्रेक डाउन

'एक शांत वाक्य में उस पिता ने दुनिया का सारा बोझ अपनी बेटी के कंधों से हटा कर अपने कंधों पर ले लिया। ये है असली पिता।'

'काश मेरे पापा भी कभी ऐसा बोलते... मैंने तो सिर्फ 'टॉप करो, डॉक्टर बनो' ही सुना है।'

'अगर हर बच्चे के माता-पिता ऐसे सपोर्टिव होते, तो डिप्रेशन और सुसाइड के केस आधे रह जाते।'

'ये वीडियो हर उस बच्चे को दिखाओ जो रात में चुपके से रोता है कि 'मुझे कुछ नहीं आता'।'

'पापा ने एक लाइन में पूरी जिंदगी का फलसफा दे दिया - 'मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं'। मतलब - जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।'

असल जिंदगी में भी ऐसे पिता हैं, बस उनकी कहानियां कम वायरल होती हैं

इस वीडियो ने एक बड़ा सवाल फिर से उठा दिया - हम बच्चों पर कितना दबाव डाल रहे हैं? 2024 के ठउफ्ह डेटा के मुताबिक, 18-30 साल के युवाओं में सुसाइड का दूसरा सबसे बड़ा कारण 'करियर/पढ़ाई का प्रेशर' है।

कोचिंग सिटी कोटा में पिछले 3 सालों में 70+ बच्चों ने प्रेशर की वजह से जान दे दी।

अधिकतर केस में पैरेंट्स का एक ही जवाब - 'हम तो बेस्ट चाहते थे।'

लेकिन इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि 'बेस्ट' का मतलब सिर्फ क्क्ळ-मेडिकल नहीं होता। बेस्ट का मतलब है - बच्चे का मानसिक सुकून, उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशी।

संदेश साफ है - प्रेशर मत दो, सपोर्ट दो

ये वीडियो सिर्फ एक पिता-बेटी की बातचीत नहीं, बल्कि आज के हर घर के लिए एक सबक है। अगर आपका बच्चा तनाव में हैं, तो उसे डांटने की बजाय एक बार जरूर बात करें, उसे समझें। क्योंकि कभी-कभी करियर से ज्यादा जरूरी होता है - एक भरोसे का हाथ और एक सुकून भरी आवाज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पापा भी ऐसे हैं? कमेंट में जरूर बताएं।

# जल्द गूंजेगी रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा के घर शहनाई?

(जीएनएस)।

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में मजबूत पहचान बना चुकीं रश्मिका मंदाना हाल ही में अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में हैं। लंबे समय से यह खबरें सामने आती रही हैं कि वह अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ रिश्ते में हैं। अब, उनकी सगाई और शादी की अफवाहों ने प्रशंसकों को और भी उत्साहित कर दिया है।

हाल ही में दिए गए एक मैगजीन इंटरव्यू में रश्मिका ने पहली बार शादी को लेकर प्रतिक्रिया दी। जब उनसे सीधे तौर पर सवाल किया गया कि शादी कब करने की योजना है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा-"इस बारे में हम खुद बताएंगे।" उनके इस जवाब ने संकेत दिया कि शादी को लेकर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यह जोड़ा फरवरी 2025 में शादी के बंधन में बंध सकता है। हालांकि दोनों की ओर से अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रशंसकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है।

उदयपुर में हो सकती है शाही शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका और विजय उदयपुर में एक भव्य लेकिन निजी समारोह में विवाह कर सकते हैं। शादी में सिर्फ परिवार और बहुत करीबी दोस्त शामिल होंगे। जगह और तारीख को लेकर अभी गोपनीयता बरती जा रही है, जिससे अंदाजे और भी मजबूत हो गए हैं।

'गीता गोविंदम' से शुरू हुई नजदीकियां

इस रिश्ते की चर्चा 2018 की सुपरहिट फिल्म 'गीता गोविंदम' के समय से शुरू हुई थी। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, और 2019 में आई फिल्म 'डियर कॉमरेड' ने इन खबरों को और हवा दी। हालांकि दोनों अक्सर साथ छुट्टियों पर जाते देखे गए और एक जैसी लोकेशन से तस्वीरें भी साझा कीं, लेकिन किसी ने भी अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया।

रश्मिका का करियर ग्राफ लगातार ऊंचा

व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ रश्मिका का फिल्मी करियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साउथ फिल्मों से शुरूआत कर वह अब बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी हैं। इस साल विक्की कौशल के साथ उनकी फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। वहीं आयुष्मान खुराना के साथ 'थामा' को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला।

# पुतिन की इस रहस्यमयी ट्रेन से क्यों डरती है दुनिया ? सीक्रेट लाइफ का चौंकाने वाला खुलासा!

(जीएनएस)।

दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में गिने जाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (श्र्रै ढ४३ल्ल) के हर कदम पर दुनिया की नजर रहती है। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति जितनी नियंत्रित होती है, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी और गुप्त है। जब भी पुतिन किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके फैसले और उनके यात्रा के साधन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं।

राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत के राजकीय दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इस यात्रा से ठीक पहले, रूस की संसद (स्टेट ड्यूमा) ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते RELOS को मंजूरी दी है।

यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं, युद्धपोतों और सैन्य विमानों को संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण या आपदा राहत के दौरान रसद सहायता (लॉजिस्टिक्स सपोर्ट) प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह समझौता सैन्य सहयोग और एयरस्पेस तथा बंदरगाहों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सीक्रेट लाइफ का राज खोलती पुतिन की 'घोस्ट ट्रेन'

भारत के साथ इस हाई-प्रोफाइल कूटनीति के बीच, एक चीज है जो पुतिन के अति-सुरक्षित लाइफस्टाइल का राज खोलती है- वह है उनकी रहस्यमयी और खास तौर पर डिजाइन की गई ट्रेन। यह सिर्फ एक आरामदायक सवारी नहीं है, बल्कि सुरक्षा का ऐसा अभेद्य किला है, जिसे खुफिया एजेंसियों और ट्रैकिंग से बचने के लिए डिजाइन किया गया है।

क्यों कहा जाता है इसे 'घोस्ट ट्रेन'?

पूर्व अधिकारियों के खुलासे और लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, पुतिन अब हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन से यात्रा (देश के घरेलू दौरे) करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि:

1. ट्रैकिंग से बचाव: एक विमान के उड़ान भरते ही वह फ़्लाइट रडार पर आ जाता है, लेकिन ट्रेन का उपयोग इन गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जाता है।

# यूपी में घुसपैठियों पर योगी सरकार का 'सर्जिकल स्ट्राइक'! क्या है रोहिंग्या-बांग्लादेशी को खदेड़ने का 'एसआईआर' प्लान

(जीएनएस)।

कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य, जहां सीमापार से आने वाले अवैध घुसपैठिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हों, बल्कि नौकरियों और संसाधनों पर भी कब्जा जमा रहे हों। उत्तर प्रदेश- जो नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है और आठ राज्यों से घिरा है- अब ऐसे 'अनचाहे मेहमानों' के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'सूची, जांच, रिटर्न'- यानी एसआईआर- की रणनीति अपनाते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कस दिया है। 17 नगर निकायों में सफाईकर्मी-मजदूरों की स्कैनिंग, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, और लखनऊ की झुग्गियों में छापेमारी - यह सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का किलेबंदी है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश- 'अवैध घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता।' आइए, इस एक्सप्लेनर में समझते हैं - यह एक्शन क्या है, क्यों है, और कैसे चलेगा...

क्या है 'एसआईआर' रणनीति? योगी सरकार का तीन-चरणीय हथियार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों (DMs) को निर्देश दिए थे - अवैध घुसपैठियों की तत्काल पहचान करें, अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं, और कानूनी प्रक्रिया से निर्वासित करें। अब 3 दिसंबर को इसे और मजबूत किया गया:- 17 प्रमुख नगर निकायों (जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, गोरखपुर) में सफाईकर्मी, ठेके पर मजदूर या अन्य निम्न-स्तरीय नौकरियों में लगे रोहिंग्या-बांग्लादेशी मूल के लोगों की विस्तृत सूची तैयार करें। यह सूची संबंधित मंडलायुक्त और आईजी को सौंपी जाएगी, जो पहचान की गई महिलाओं/पुरुषों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करेंगे।

चरण 1: सूची - पहचान का फंडा

17 नगर निकायों में फील्ड सर्वे शुरू। सफाई विभाग, निर्माण स्थल, झुग्गी-झोपड़ियां - हर जगह दस्तावेज चेक। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र - सबकी सत्यापन। संदिग्ध दस्तावेजों की जांच संबंधित जिलों/थानों से। उद्देश्य: फर्जी आईडी से सरकारी लाभ (जैसे पेंशन, सब्सिडी) लेने वालों को बेनकाब करना।

# प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र ने आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शताब्दी स्थापना सप्ताह को संबोधित किया

■ डॉ. पी.के. मिश्र ने आईआईटी धनबाद से प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने का आ'ान किया

■ वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है: डॉ. पी.के. मिश्र

■ कई देश, खासकर विकासशील देशों में, अब भारत को विश्व बंधु - आधुनिक क्षमता को सभ्यतागत ज्ञान के साथ मिलाने वाला एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं : डॉ. पी.के. मिश्र

■ डॉ. पी.के. मिश्र ने आईआईटी धनबाद से भारत की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद के शताब्दी फाउंडेशन वीक में उद्घाटन भाषण दिया। शिक्षकों, छात्रों, पूर्व-छात्रों और खास मेहमानों से बात करते हुए, डॉ. मिश्र ने 2047 तक विकसित भारत बनने की भारत की यात्रा में आईआईटी धनबाद की अहम भूमिका पर जोर दिया।

डॉ. पी.के. मिश्र को इस साल की शुरूआत में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

संस्थान की 100 साल की विरासत के जश्न में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, खनन, ऊर्जा, पृथ्वी विज्ञान और प्रयुक् त अभियंत्रण (एप्लायड इंजीनियरिंग) में इसके बहुत बड़े योगदान को ध् यान में रखते हुए, डॉ. मिश्र ने याद दिलाया कि आईआईटी धनबाद एशिया में खनन की शिक्षा में अग्रणी रहा है और इसने कोल इंडिया, ओएनजीसी, जीएसआई, सीएमपीडीआई और एनटीपीसी जैसे राष् ट्रीय संस्थानों को लगातार विशेषज्ञता दी है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के इसके नतीजों ने खान सुरक्षा, कोयला निकालने, तेल और गैस तथा खनिज को लाभदायक बनाने में राष्ट्रीय मानदंड को आकार दिया है। डॉ. मिश्र ने कहा, 'एक शताब्दी सिर्फ एक मील का पत्थर भर नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब ज्ञान का इस्तेमाल सकारात् मक सामाजिक नतीजों के लिए जनहित के तौर पर किया जाता है, तो दृढ़ संकल् प से क्या हासिल किया जा सकता है।' उन्होंने संस् थान से भारत के एक विकसित देश बनने के दीर्घकालिक विजन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को दशार्ने को कहा।

प्रधानमंत्री के 2047 के भारत के विजन पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मिश्र ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन बनाते हुए एक विकसित देश का दर्जा हासिल करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में आगे रहना है। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगी, अर्थव्यवस्था सबको साथ लेकर चलने वाली और नई होगी एवं राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी।

पिछले 11 सालों में भारत की आर्थिक प्रगति पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री के विजन को नवाचार और अन्वेषण पर आधारित बताया। उन्होंने इस विजन के चार स्तंभ बताए: प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का लाभ, वैश्विक चुनौतियों का सामना करना और अंतिम दूरी तक लाभ पहुंचने की गारंटी करना। उन्होंने यह स्वीकार किया कि महामारी, व्यापार युद्ध, भू-राजनैतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हुआ।

# स्थानीय विकास में कोयला खदानों का योगदान

(जीएनएस)।

झारखंड के मगध और आम्रपाली खदानें मिलकर 2024-25 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 50% योगदान देती हैं, इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप विद्युत उत्पादन के लिए सुनिश्चित कोयला आपूर्ति के राष्ट्रीय उद्देश्य का समर्थन करती हैं। मगध और आम्रपाली कोयला खदानों के अनुमानित खनिज भंडार क्रमशः 854.91 मिलियन टन और 456.34 मिलियन टन हैं और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इनसे क्रमशः 2,812 करोड़ रुपये और 2,367 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री आय उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये खदानें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी) और नजदीकी ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका सहायता प्रदान करके स्थानीय विकास में योगदान देती हैं। मगध-संघमित्रा क्षेत्र में 808 और आम्रपाली-चन्द्रगुप्त क्षेत्र में 210 व्यक्तियों को रोजगार देने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

नमचिक नामफुक कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी, क्योंकि यह प्रति वर्ष 0.2 मिलियन टन (एम टी पी ए) कोयले का योगदान करेगी। यह नियमित आपूर्ति राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक विश्वसनीय रूप से पूरा करने में मदद करेगी। इस खदान में अनुमानित भौगोलिक भंडार 14.97 एमटी हैं और यह लगभग 270 लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ सालाना 173 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करेगी।

मिशन ग्रीन (प्रकृति को बढ़ाना, पुनर्स्थापित करना, समृद्ध करना और सशक्त बनाना) के तहत, कोयला क्षेत्र, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) ने, अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), ने कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। मिशन ने खनन-पश्चात खदान और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों को सतत पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए पांच वर्ष का विजन प्रस्तुत किया गया है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मिशन का ध्यान खनन क्षेत्रों और उनके आसपास व्यापक वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, सतत खदान-जल का सतत उपयोग और चक्रीय संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने पर है। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से विविधता लाने के लिए खदान-आधारित पर्यटन और हरित-अर्थव्यवस्था मॉडल जैसी पहलें भी आगे बढ़ाई जा रही हैं।

# परमाणु ऊर्जा विभाग और रोसाटॉम के बीच समझौता

(जीएनएस)।

परमाणु ऊर्जा विभाग और रोसाटॉम के बीच एक बैठक हुई जिसमें बड़े और छोटे पैमाने के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का विकास और परमाणु ईंधन चक्र में सहयोग जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष रूप से, भारत में उपकरण उत्पादन के स्थानीयकरण के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहयोग के लिए चर्चा के नए क्षेत्रों में से एक भारत में रूसी डिजाइन के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) का निर्माण शामिल है।

परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए बजट 2025-26 की घोषणा में, 2033 तक पांच स्वदेशी एसएमआर के विकास और तैनाती पर जोर दिया गया है, जिसका परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है।

बीएआरसी ने एसएमआर पर डिजाइन और विकास कार्य शुरू किया है,

200 मेगावाट भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200),

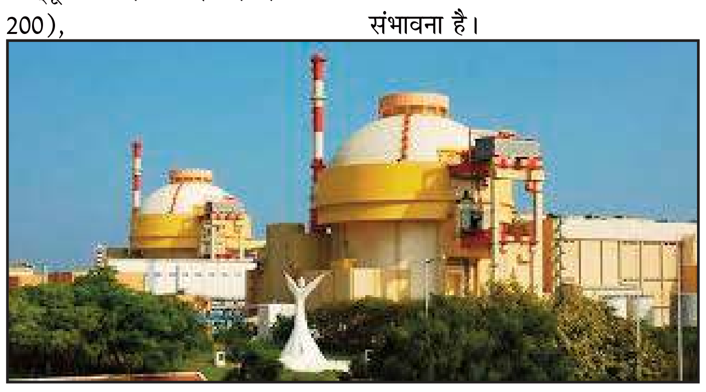

55 मेगावाट लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर-55), और

5 मेगावाट तक उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए है।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए इन रिएक्टरों की प्रमुख इकाइयों का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के स्थल पर करने का प्रस्ताव है। परियोजना की स्वीकृति मिलने के बाद, डिमोंस् ट्रेशन रिएक्टरों का निर्माण 60 से 72 महीनों में होने की संभावना है।

उद्योगों द्वारा निजी इस् तेमाल हेतु भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) के संबंध में, एनपीसीआईएल ने सरकार द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक मॉडल के अनुरूप 31 दिसंबर, 2024 को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) किया। फरवरी 2025 में एक प्रस्ताव-पूर्व बैठक आयोजित की गई, जहां इच्छुक उद्योगों के प्रश्नों का समाधान किया गया। विभिन्न इच्छुक उद्योगों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों पर स्पष्टीकरण संकलित किए गए और एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए। इसके अलावा, उद्योगों के अनुरोधों के आधार पर, आरएफपी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मसौदा वर्तमान में प्रक्रिया और तैयारी के उन्नत चरण में है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की अंतिम टिप्पणियों और सुझावों को क्रमिक रूप से शामिल किया जा रहा है, साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कानूनी अनुपालन हेतु इसकी जांच भी की जा रही है। विधेयक के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में सरकार के नीतिगत निर्देशों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले यथोचित तरीके से शामिल किया जा रहा है।

# भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दक्षता और नवाचार महत्वपूर्ण : केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल

**भारतीय उद्योग को वैश्विक विकास के प्रति प्रतिस्पर्धी और उत्तरदायी होना चाहिए: श्री गोयल**

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग६मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित इंडियाएज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के प्रमुख उत्प्रेरकों के रूप में नवाचार, गुणवत्ता, डिजाइन, स्थिरता और दक्षता के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में हाल के विकास

रुझानों का उल्लेख किया और बताया कि भारत का विनिर्माण उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स, श्वेत वस्तुओं, रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स जैसे नए क्षेत्रों में विविधता पूर्ण हो गया है।

मंत्री महोदय ने उद्योग जगत के लिए प्रतिस्पर्धी बने रहने और वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील बने रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाल के व्यवधानों ने सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के महत्व को रेखांकित किया है और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया। उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया जहाँ घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक नियंत्रण आवश्यक है।

श्री गोयल ने कहा कि विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि से सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि को और गति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, उसे घरेलू अर्थव्यवस्था में भी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के लिए खुला रहना होगा।

# 'गंदे पैंट पहनने वाले', जया बच्चन का बयान सुन अब पपराजी ने दी खुली धमकी, जिसे सुन बैकफुट पर आएंगी एक्ट्रेस?

(जीएनएस)।

जया बच्चन और पपराजी के बीच चले आ रहे तनाव ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। हाल ही में जया बच्चन ने पपराजी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर सवाल उठाए। उनके इन बयानों से पपराजी समुदाय में भारी नाराजगी फैल गई, जिसके बाद उन्होंने जया बच्चन और उनके पोते अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म 'इक्कीस' के प्रमोशन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।

इवेंट के दौरान दिए बयान बने विवाद की वजह

मामला तब भड़का जब जया बच्चन एक इवेंट में पत्रकार बरखा दत्त से बातचीत कर रही थीं। यहां उन्होंने पपराजी को "गंदे पैंट पहनने वाले" और "मोबाइल लेकर खड़े होने वाले" लोग बताते हुए कहा कि क्या ऐसे लोग देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि इस समुदाय की शिक्षा और बैकग्राउंड क्या है। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक हलचल मचा दी और पपराजी ने इसे सीधे अपमान के रूप में लिया।

पपराजी की तीखी प्रतिक्रिया और बहिष्कार की धमकी

पपराजी प्रतिनिधि पल्लव पालीवाल ने जया बच्चन के बयान की निंदा करते हुए कहा कि "उन्होंने जो कहा, वह अनुचित है।" उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पपराजी 'इक्कीस' के प्रमोशन को कवर न करें, तो इसका प्रभाव साफ दिखाई देगा। पालीवाल का कहना था कि बड़े मीडिया हाउस कई बार बोल्ड कवरेज नहीं करते, लेकिन पपराजी लगातार जमीन पर रहकर सेलेब्स को कवर करते हैं।

पालीवाल ने जया के कपड़ों को लेकर दिए बयान पर भी नाराजगी जताई और कहा कि मेहनत करने वालों को उनके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही जया पपराजी को "मीडिया" न मानें, लेकिन डिजिटल युग में यह सोशल मीडिया का अहम हिस्सा हैं।

मानव मंगलानी और वरिंदर चावला का पक्ष

पपराजी मानव मंगलानी ने जया बच्चन के प्रति सम्मान जताया, लेकिन कहा कि वह डिजिटल दौर के साथ स्वयं को ढालने में पीछे रह गई हैं। उन्होंने साफ किया कि कई बार यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अनुचित व्यवहार करते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री की छवि प्रभावित होती है।

वहीं अनुभवी पपराजी वरिंदर चावला ने बहिष्कार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सेलेब्रिटीज की इच्छा का सम्मान किया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन का एक विवादित वीडियो पोस्ट नहीं किया। चावला ने यह भी स्वीकार किया कि पपराजी समुदाय में खामियां हैं, लेकिन जया बच्चन को हर व्यक्ति को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। मामला फिलहाल गरमाया हुआ है। पपराजी समुदाय एकजुट होकर जया बच्चन का बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी है। देखना यह होगा कि क्या यह विवाद सुलझेगा या आगे और गहराएगा।

# शुभमन गिल की हुई वापसी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 टीम घोषित, ईशान किशन का शतक गया बेकार

(जीएनएस)।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है, जो इस सीरीज को और भी दिलचस्प बना देगा। वनडे सीरीज से बाहर रहने वाले शुभमन गिल वापस आ गए हैं, हालांकि उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर है। फिट नहीं होने पर वह नहीं खेलेंगे।

बल्लेबाजी में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे, वहीं ऑलराउंड विभाग में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे अनुभवी गेंदबाजों के हाथों में रहेगी।

पांच मैचों की टी20 सीरीज में संजू सैमसन और जितेश शर्मा के रूप में दो विकेटकीपर शामिल किये गए हैं। ईशान किशन की एक बार फिर से अनदेखी हुई है। मौजूदा सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किशन ने धमाकेदार शतक जड़कर टीम में वापसी करने के लिए दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सलेक्टर्स ने उनको जगह नहीं दी।

टी20 सीरीज का आगाज कटक से होगा, यह मुकाबला 1 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद अन्य चार मुकाबले न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ, अहमदाबाद में खेले जाएंगे।

ये मैच 11, 14, 17 और 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।

भारतीय टीम में ये खिलाड़ी शामिल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर

# वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना

(जीएनएस)।

सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए 9 दिसंबर 2020 को पीएम-वाणी योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के उद्देश्यों के अनुरूप पीएम-वाणी ढांचे का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना का निर्माण करना है। यह ढांचा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को न्यूनतम नियामक निगरानी के साथ, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) के संयोजन के अंतर्गत वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है। इससे स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 26.11.2025 तक राज्यवार पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या अनुलग्नक-कमें संलग्न है ।

पीएमवाणी योजना के अंतर्गत ग्राहकों को वाई-फाई सेवाएँ पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह पीडीओए (पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स) के एजेंट होते हैं। 26 नवंबर 2025 तक वर्तमान में चालू पीडीओ (वाई-फाई हॉटस्पॉट) की कुल संख्या 3,91,599 है।

दूरसंचार विभाग ने पीएम वाणी के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स के प्रसार से संबंधित दबावपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए वर्तमान पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) ढांचे में 16.09.2024 को निम्नलिखित प्रमुख सुधार पेश किए:

- पीडीओ (पब्लिक डेटा ऑफिस) को नियमित एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से पीएम वाणी की पेशकश करने की अनुमति दी गई। इससे उनकी लागत कम हो जाएगी।
- पीडीओ को अपने एकाधिक एक्सेस प्वाइंट को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की ओर एकल बैकहॉल में एकत्रित करने की अनुमति दी गई। इससे व्यापक वाई-फाई हॉटस्पॉट का निर्माण किया जा सके।
- वर्तमान घरेलू या व्यावसायिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स को बड़े पीएम-वाणी नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति दी गई।